

मिलेगी EV पर सब्सिडी

सीएम योगी ने किया ऐलान, रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस 2027 तक माफ

एनपीटी ब्यूरो, लखनऊ

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग को देखते हुए 13 अक्टूबर, 2024 तक सविस्तर का सत्र मिला जाएगा। EV की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की मांगी का सत्र अक्टूबर, 2027 तक लिये जा सकेगा। रजिस्टर की सलाह देती है कि अधिकांश ने इसकी खरीद की। उन्होंने 50 नए रोडवेज बसें, 38 इंटरसिटी वाहनों की हरी झंडी दिखाई और EV सविस्तर जारी की। अक्सर बनाए गए औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी के मुताबिक पिछले राजस्थान के मुताबिक 13 अक्टूबर, 2023 तक वाहनों की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं को सविस्तर का सत्र मिला जा रहा।

मुल्यमंत्रि आन्सुवर हर हए कार्यक्रम के दौरान 4,100 EV स्वामियों के खाते में 13 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की गई। सीएम ने 10 लोगों को खुद पेंक दी। इसमें यश त्रिपाठी, शक्ति स्वामी, सन्दा, सौम्य शुक्ल, अनिल चौधरी, अनुपम सिंह, राजशेखर प्रधान, अनिल गुप्ता, अमर मेहरोत्रा, अनुर सिंह व सिमिता शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग व भारतीय सूजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच एक द्वाइकी टेक्नो ऐड टेस्टिंग डेस्टिनेट ऑटोमेशन और संवर्धन के लिए एमओयू साइन किया गया। ये डेस्टिनेट औरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, मधुवा व बाराबंकी में खुले। महिला चालकों के डिप्लोमा के लिए उच्च शिक्षा विभाग



मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को हुए कार्यक्रम में योगी ने इलेक्ट्रिक वाइकल खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी के चेक सौंपे।

दो लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत

सीएम ने प्रदेश के शहरों और गांवों को कनेक्ट करने के लिए दो लाख से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की आवश्यकता है। इससे रोजगार सृजन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बेहतरीन सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक करोड़ की बस खरीदने पर 20 लाख रुपये सब्सिडी सरकार दे रही है। इससे टीजत समेत अन्य खर्चों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने हर पेट्रोल पर पर EV चार्जिंग मशीन के लिए प्रयास करने को भी कहा।

मिलान बीच सम्मेलित हुआ। सीएस ने कहा कि स्वयंसेवी समूहों की महिलाओं को इसमें शामिल होना।

सड़क हादसे रोकना बड़ा चैलेंज : सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को रोकना बड़ा चैलेंज है। अधिकतर हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। इसलिए दख न हो, तब भी यह दुर्घटना होती है। सीएम ने सड़क सुरक्षा और जनजागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि बीजिंग में दो साल में 24

सड़क हादसों में हर साल सड़क में 20-22 हजार लोगों की जान जाती है। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयालकर सिंह, मुख्य सचिव दुर्गालकर मिश्र, औद्योगिक व आवासन आगुस्त मन्वेज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव (परिवहन) वेन्स्टनर लु, परिवहन निगम के एमडी मन्सूम अली सरवर, परिवहन आगुस्त चंद्रभूषण सिंह, मार्गति सुकुनी इंडिया लिमिटेड के एंजिनियरिंग डिपार्टमेंट (कॉरपोरेट अफेयर्स) रहल भरती व वाइस प्रेसिडेंट (सीएसओ) तरण

हर जिले में तैनात
होंगे एआरटीओ
रोड सेफ्टी

लखनऊ : सीएन येनी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क हादसों को न्यूनतम करने के लिए हर जिले में एआरटीओ रोड सेफ्टी की कैंपेनी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग से इस संघी में जल्द से जल्द प्रत्यक्ष फैसल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाए। साथ ही सड़कों की इंजिनियरिंग और इमारतों की चेकर पर भी फोकस किया जाए। सीएन ने 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा फसलगत मनाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को हुई उच्च प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएन ने कहा कि सड़क की सुरक्षा हो चुकी है और इस दौरान सड़क हादसों जकड़ होते हैं। इसे न्यूनतम करने के लिए हमें जागरूकता, शिक्षा, फर्निचर, इंजीनियरिंग और इमारतों की चेकर पर फोकस करना होगा। युवा सड़क पर जातन दुर्घटनाओं वाले राज्यों में तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में राष्ट्रीय और राज्य गरीब पर हादसों में दो-दो